International Journal on Science and Technology (IJSAT)
E-ISSN: 2229-7677 ● Website: www.ijsat.org ● Email: editor@ijsat.org

विकसित भारत @2047 के परिप्रेक्ष्य में बिहार में मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा – चुनौतियाँ और संभावनाएँ

राजन कुमार [1] डॉ प्रशांत कुमार [2]

[1]शोधार्थी [2]सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष
विश्वविद्यालय भूगोल विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश

विकसित भारत @2047 की संकल्पना भारत को आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी तथा मानवीय विकास के उच्च स्तर पर स्थापित करने की दीर्घकालिक दृष्टि प्रस्तुत करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा की भूमिका केन्द्रीय है। बिहार जैसे राज्य, जहाँ विशाल युवा जनसंख्या के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक विषमताएँ, शैक्षिक असमानता तथा कौशल–अभाव जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं, वहाँ मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ करना राष्ट्रीय विकास रणनीति का अनिवार्य घटक बन जाता है। प्रस्तुत शोध–पत्र में बिहार में शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए विकसित भारत @2047 के संदर्भ में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों और संभावनाओं की पहचान की गई है। अध्ययन यह दर्शाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल–आधारित प्रशिक्षण, तकनीकी एवं डिजिटल शिक्षा, तथा महिला एवं वंचित वर्गों की भागीदारी को सुदृढ़ किए बिना समावेशी एवं सतत विकास संभव नहीं है।

मुख्य शब्द – मानव संसाधन विकास, शिक्षा, बिहार, विकसित भारत @2047, कौशल विकास।

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में मानव संसाधन उसकी सबसे मूल्यवान पूँजी मानी जाती है। प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता के बावजूद वे देश तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति कर पाए हैं, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास के माध्यम से अपने मानव संसाधनों को सुदृढ़ किया है। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत "विकसित भारत @2047" की परिकल्पना देश को एक समावेशी, आत्मनिर्भर, नवाचारी तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) एवं शिक्षा को केन्द्रीय स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया है।

मानव संसाधन विकास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि "यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति की ज्ञान, कौशल, क्षमता और अभिवृत्तियों का निरंतर विकास किया जाता है, ताकि वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर उत्पादक बन सके" (हरबिसन, 1973)। इसी प्रकार अमर्त्य सेन के अनुसार, विकास का वास्तविक अर्थ केवल आय–वृद्धि नहीं, बल्कि मानव की क्षमताओं और विकल्पों का विस्तार है (सेन, 1999)। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि शिक्षा मानव संसाधन विकास का मूल आधार है, क्योंकि वही मानव की क्षमताओं को सशक्त बनाती है।

भारत के संदर्भ में यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग (15–59 वर्ष) में है। यह स्थिति भारत को एक जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) प्रदान करती है, परंतु यदि यह विशाल जनसंख्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल से वंचित रह जाए, तो यही लाभांश विकास में बाधा भी बन सकता है (Planning Commission, 2013)।

इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बिहार की स्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बिहार ऐतिहासिक रूप से नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात ज्ञान केंद्रों की भूमि रहा है, किंतु आधुनिक काल में यह राज्य शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.8 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत (74.0 प्रतिशत) से काफी कम है। विशेष रूप से महिला साक्षरता दर (53.3 प्रतिशत) का निम्न स्तर राज्य में लैंगिक असमानता और मानव संसाधन विकास की कमजोरी को दर्शाता है (Census of India, 2011)।

यद्यपि हाल के वर्षों में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के नामांकन में वृद्धि हुई है, तथापि शिक्षा की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा में नामांकन, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल–आधारित प्रशिक्षण की स्थिति अभी भी अपेक्षित स्तर से नीचे बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा और रोजगार के बीच असंतुलन, प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव तथा बड़े पैमाने पर बाह्य प्रवास जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं (NITI Aayog, 2021)।

विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि बिहार जैसे राज्य अपनी मानव संसाधन क्षमता को सुदृढ़ करें। इसके लिए शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण, कौशल विकास, डिजिटल एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार, तथा महिला एवं वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि कहा गया है;

"शिक्षा वह शक्ति है जो समाज की संरचना को बदलने की क्षमता रखती है।"

अतः यह अध्ययन विकसित भारत @2047 के परिप्रेक्ष्य में बिहार में मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास करता है कि वर्तमान चुनौतियों के बावजूद किस प्रकार नीतिगत एवं संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से राज्य को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में सशक्त रूप से सम्मिलित किया जा सकता है।

साहित्य समीक्षा

मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा के अंतर्संबंध पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक साहित्य उपलब्ध है। हरबिसन एवं मायर्स (1973) ने मानव संसाधन विकास को आर्थिक प्रगति की आधारशिला मानते हुए शिक्षा और प्रशिक्षण को उत्पादक क्षमता बढ़ाने का प्रमुख साधन बताया है। अमर्त्य सेन (1999) के Capability Approach में यह स्पष्ट किया गया है कि वास्तविक विकास का माप केवल आय नहीं, बल्कि मानव की क्षमताओं, विकल्पों और स्वतंत्रताओं का विस्तार है, जिसमें शिक्षा की भूमिका केंद्रीय है। भारतीय संदर्भ में द्रेज और सेन (2013) ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अपर्याप्त निवेश क्षेत्रीय असमानताओं को और गहरा करता है। नीति आयोग (2021) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश तभी विकास में परिवर्तित हो सकता है, जब शिक्षा को कौशल–आधारित और रोजगारोन्मुख बनाया जाए। बिहार के संदर्भ में विभिन्न अध्ययनों (कुमार, 2016; सिंह, 2019) ने यह रेखांकित किया है कि साक्षरता दर में वृद्धि के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता, महिला शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी मानव संसाधन विकास में प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। हाल के शोध यह भी संकेत देते हैं कि डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित नीतियाँ बिहार को विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करने की महत्वपूर्ण संभावनाएँ प्रदान करती हैं।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध के लिए बिहार को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक स्थलरुद्ध राज्य है, जिसकी भौगोलिक स्थिति लगभग 24°20′ से 27°31′ उत्तरी अक्षांश तथा 83°19′ से 88°17′ पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। गंगा नदी बिहार को पूर्व–पश्चिम दिशा में विभाजित करती है, जिससे राज्य में भौगोलिक एवं सामाजिक विविधता परिलक्षित होती है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10. 4 करोड़ है, जिसमें युवाओं का अनुपात अत्यधिक है, जो राज्य को महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय क्षमता प्रदान करता है। कृषि–प्रधान अर्थव्यवस्था, ग्रामीण आबादी का उच्च प्रतिशत, अपेक्षाकृत निम्न साक्षरता दर तथा शिक्षा एवं कौशल विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ बिहार को मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त एवं प्रतिनिधि क्षेत्र बनाती हैं, विशेषकर विकसित भारत @2047 के परिप्रेक्ष्य में।

अध्ययन के उद्देश्य

- बिहार में मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
- विकसित भारत @2047 के परिप्रेक्ष्य में बिहार में मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा से संबंधित प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।
- बिहार में शिक्षा, कौशल विकास एवं तकनीकी प्रशिक्षण की संभावनाओं का आकलन करना, जिससे राज्य की मानव संसाधन क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके।

आँकड़ों के स्रोत एवं शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में बिहार में मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण करने हेतु द्वितीयक आँकड़ों का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है। आँकड़े भारत की जनगणना 2001 एवं 2011, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, शिक्षा से संबंधित सरकारी रिपोर्टों, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, तथा राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय पत्रिकाओं एवं रिपोर्टों से संकलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विषय से संबंधित पुस्तकों, शोध–पत्रों, जर्नल लेखों, शोध प्रबंधों एवं विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों का भी संदर्भ लिया गया है, जिससे अध्ययन की सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ किया जा सके।

शोध पद्धति की दृष्टि से यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। संकलित आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, अनुपात एवं तुलनात्मक विधि के माध्यम से किया गया है, ताकि शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास में समयानुसार परिवर्तन तथा क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट किया जा सके। अध्ययन में विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों के संदर्भ में बिहार की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु तुलनात्मक विश्लेषण तथा तार्किक व्याख्या विधि अपनाई गई है। इस प्रकार, उपलब्ध आँकड़ों और विश्लेषणात्मक पद्धतियों के माध्यम से बिहार में मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मानव संसाधन विकास – अवधारणा एवं सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

मानव संसाधन विकास (Human Resource Development–HRD) आधुनिक विकास चिंतन की एक केंद्रीय अवधारणा है, जिसमें मानव को केवल उत्पादन का साधन न मानकर विकास का लक्ष्य और साधन दोनों के रूप में स्वीकार किया गया है। मानव संसाधन विकास का आशय उस निरंतर प्रक्रिया से है, जिसके माध्यम से मानव की ज्ञान, कौशल, क्षमता, कार्यकुशलता, स्वास्थ्य, दृष्टिकोण तथा नवाचार क्षमता का समग्र विकास किया जाता है, ताकि वह व्यक्तिगत उन्नति के साथ–साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान दे सके। हरबिसन और मायर्स (1973) के अनुसार, "मानव संसाधन विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने नागरिकों के ज्ञान और कौशल

का विकास करता है, ताकि वे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभा सकें।" यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि मानव संसाधन विकास केवल शिक्षा या प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया है।

सैद्धांतिक दृष्टि से मानव संसाधन विकास की जड़ें मानव पूँजी सिद्धांत (Human Capital Theory) में निहित हैं, जिसे शुल्त्ज (1961) और बेकर (1964) ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय निवेश है, जो भविष्य में उच्च उत्पादकता और आय के रूप में प्रतिफल देता है। आगे चलकर यह दृष्टिकोण और व्यापक हुआ, जब अमर्त्य सेन (1999) ने क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach) प्रस्तुत किया। सेन के अनुसार, विकास का वास्तविक अर्थ केवल आय में वृद्धि नहीं, बल्कि मानव की क्षमताओं, स्वतंत्रताओं और जीवन–चयन के अवसरों का विस्तार है। इस दृष्टि से शिक्षा मानव संसाधन विकास का सबसे सशक्त माध्यम बन जाती है, क्योंकि वही व्यक्ति को सोचने, निर्णय लेने और सशक्त बनने की क्षमता प्रदान करती है।

मानव संसाधन विकास की अवधारणा का संबंध केवल आर्थिक विकास से ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, समावेशन और सतत विकास से भी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रतिपादित मानव विकास दृष्टिकोण यह मानता है कि किसी भी देश की प्रगति का आकलन केवल सकल घरेलू उत्पाद से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे मानवीय सूचकों से किया जाना चाहिए। इसी विचारधारा के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक (HDI) की अवधारणा विकसित हुई, जिसने मानव संसाधन विकास को विकास विमर्श के केंद्र में स्थापित किया।

भारतीय संदर्भ में मानव संसाधन विकास का विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि देश की विशाल जनसंख्या को यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त न हों, तो वह विकास का अवसर बनने के बजाय बोझ में परिवर्तित हो सकती है। अतः मानव संसाधन विकास को एक रणनीतिक राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। विकसित भारत @2047 की परिकल्पना भी इसी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी दक्षता और मानव क्षमता का विस्तार ही भारत को दीर्घकालिक रूप से विकसित राष्ट्र बना सकता है। इस प्रकार मानव संसाधन विकास की अवधारणा न केवल सैद्धांतिक रूप से सुदृढ़ है, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी राष्ट्रीय विकास की धुरी के रूप में उभरती है।

शिक्षा और मानव संसाधन विकास का अंतर्संबंध

शिक्षा और मानव संसाधन विकास के बीच घनिष्ठ, प्रत्यक्ष एवं बहुआयामी संबंध विद्यमान है। शिक्षा वह प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा मानव की बौद्धिक क्षमता, कौशल, मूल्य–बोध तथा नवाचार क्षमता का विकास होता है, जबकि मानव संसाधन विकास शिक्षा के इन परिणामों को सामाजिक–आर्थिक प्रगति में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार शिक्षा मानव संसाधन विकास की आधारशिला है और मानव संसाधन विकास शिक्षा की व्यावहारिक परिणति के रूप में सामने आता है। जैसा कि कहा गया है, "शिक्षा मनुष्य को सक्षम बनाती है और सक्षम मानव ही विकास का वास्तविक वाहक होता है।"

मानव पूँजी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा में किया गया निवेश भविष्य में उच्च उत्पादकता, बेहतर रोजगार अवसर और आय–वृद्धि के रूप में प्रतिफल देता है (शुल्त्ज, 1961; बेकर, 1964)। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मानव संसाधन विकास के लिए आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक क्षमता एवं जीवन–कौशल प्रदान करती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक चेतना, कार्य–अनुशासन तथा व्यावसायिक अभिवृत्तियों का विकास करती है। उच्च, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा मानव को विशिष्ट कौशल, अनुसंधान क्षमता और तकनीकी दक्षता से सुसज्जित कर उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाती है। इस प्रकार शिक्षा के विभिन्न स्तर मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया को क्रमिक एवं सतत रूप प्रदान करते हैं।

वर्तमान ज्ञान–आधारित एवं प्रौद्योगिकी–प्रधान अर्थव्यवस्था में शिक्षा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र के विस्तार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के मानव संसाधन अप्रासंगिक हो सकते हैं। यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों में शिक्षा, अनुसंधान एवं कौशल विकास को आर्थिक नीति के केंद्र में रखा गया है। भारतीय संदर्भ में भी यह देखा गया है कि जिन राज्यों में साक्षरता, तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का स्तर बेहतर है, वहाँ रोजगार, आय और मानव विकास सूचकांक अपेक्षाकृत उच्च पाया गया है।

शिक्षा का मानव संसाधन विकास से संबंध केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर भी पड़ता है। शिक्षित मानव सामाजिक चेतना, लोकतांत्रिक सहभागिता, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों को भी सुदृढ़ करता है। विशेष रूप से महिला शिक्षा मानव संसाधन विकास की गति को तीव्र करती है, क्योंकि शिक्षित महिलाएँ अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करती हैं, जिससे विकास का बहुगुणक प्रभाव उत्पन्न होता है। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षा और मानव संसाधन विकास एक–दूसरे के पूरक हैं और विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन दोनों का समन्वित एवं गुणवत्तापूर्ण विकास अनिवार्य है।

बिहार में मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा की वर्तमान स्थिति

बिहार की शैक्षिक और मानव संसाधन स्थिति मिश्रित उत्कर्ष और चुनौतियों का सम्मिश्रण रह चुकी है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी और उस समय राज्य की समग्र साक्षरता दर 63.82% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 73.39% और महिला साक्षरता 53.33% रही यह राष्ट्रीय औसत (2011) से काफी नीचे का पैमाना दर्शाता है। इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि साक्षरता का विस्तार हुआ है पर गुणवत्ता, क्षेत्रीय व लैंगिक असमानता अब भी प्रमुख बाधा है।

उच्च शिक्षा में भागीदारी (Gross Enrolment Ratio — GER) के आयामी में बिहार पिछड़े राज्यों में गिना जाता है: AISHE 2021–22 के अनुसार बिहार का कुल GER लगभग 17.1% (2021–22) है, जबकि राष्ट्रीय GER 28.4% (2021–22) रहा, इस अंतर से स्पष्ट है कि उच्चतर शिक्षण में पहुँच व अवसर सीमित हैं और बड़े पैमाने पर छूट बनी हुई है। GER के निचले स्तर का सीधा प्रभाव उच्च कौशल वाले मानव संसाधन की उपलब्धता पर पड़ता है।

शैक्षिक अवसंरचना के विकास के संकेत भी मिले हैं, हालिया UDISE+ (2024–25) रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ≈94,339 स्कूल और कुल नामांकन 2.11 करोड़ छात्रों तथा लगभग 7.07 लाख शिक्षक हैं; अतः विद्यालयों की संख्या एवं नामांकन बड़े स्तर पर हैं, किन्तु छात्र–शिक्षक अनुपात (परी औसत) और अवसंरचनात्मक कमी (शौचालय, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, बिजली) जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं, जिनका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है।

आर्थिक भागीदारी के संदर्भ में महिला कार्यबल भागीदारी दर (Women's Workforce Participation Rate) बेहद कम है, कई स्रोतों ने बिहार की महिला WPR को अन्य राज्यों की तुलना में बहुत न्यून (उदाहरणतः ~2.7–2.8% के आसपास कुछ वर्षों का आँकड़ा उद्धृत) बताया है, यह संकेत करता है कि महिलाओं की शिक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के बीच बड़ा अंतर मौजूद है। महिला शिक्षा में वृद्धि के साथ भी रोजगार–संबंधी अवसरों का अभाव और सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ व्यापक चुनौती बनी हुई हैं।

समेकित रूप में, बिहार में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर नामांकन व उपलब्धता में सुधार हुआ है, पर गुणवत्ता, उच्च शिक्षा में पहुँच, कौशल–रोजगार मेल, और लैंगिक/क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी मानव संसाधन विकास की प्रमुख सीमाएँ हैं।

तालिका 1: बिहार – चुने हुए शैक्षिक व मानव संसाधन संकेतक

संकेतक	मान	वर्ष/रिपोर्ट
कुल जनसंख्या	104,099,452	Census 2011
समग्र साक्षरता दर	63.82% (पुरुष 73.39%, महिला 53.33%)	Census 2011
Gross Enrolment Ratio (Higher Education — बिहार)	17.1% (Both — 2021–22)	AISHE 2024
स्कूलों की संख्या (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक)	≈94,339 स्कूल, नामांकन ≈2.11 करोड़, शिक्षक ≈7.07 लाख	UDISE+ 2024–25
महिला कार्यबल भागीदारी दर	~2.7%–2.8%	IWWAGE, PLFS

निहित महत्व

1. उच्च शिक्षा में निम्न GER संकेत करता है कि उच्च–स्तरीय स्नातक/पोस्ट–ग्रैजुएट योग्य कार्यबल की कमी रहेगी, इससे विज्ञान, तकनीक और नवाचार–आधारित उद्योगों के लिए स्थानीय मानव संसाधन सीमित होगा।
2. महिला WPR का बहुत कम स्तर यह बताता है कि सामाजिक बाधाएँ, कौशल–निर्देश तथा रोजगार–मौकों का अभाव महिला सशक्तिकरण को रोके हुए हैं, महिला शिक्षण में निवेश का लाभ तभी वास्तविक रूप लेगा जब रोजगार–समर्थन और सामाजिक समर्थन प्रणाली भी मजबूत हों।
3. स्कूल अवसंरचना में कमियाँ (UDISE+), शौचालय, बिजली, कम्प्यूटर और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं की कमी शिक्षा की गुणवत्ता में बाधा डालती हैय इसलिए नामांकन बढ़ाने के साथ–साथ इन अवसंरचनात्मक दोषों का शीघ्र उन्मूलन आवश्यक है।

विकसित भारत @2047 के संदर्भ में प्रमुख चुनौतियाँ

विकसित भारत @2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिहार में मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा से जुड़ी कुछ संरचनात्मक एवं प्रक्रियागत चुनौतियाँ स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। ये चुनौतियाँ न केवल शैक्षिक प्रगति को सीमित करती हैं, बल्कि राज्य की जनसांख्यिकीय क्षमता को उत्पादक शक्ति में बदलने की प्रक्रिया को भी बाधित करती हैं –

- **शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय असमानता**

बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्षों में पहुँच (Access) के स्तर पर विस्तार अवश्य हुआ है, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education) आज भी क्षेत्रीय असमानताओं से गंभीर रूप से प्रभावित है। ग्रामीण, दूरस्थ, बाढ़–प्रभावित तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ, भौतिक अवसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता तथा अधिगम–स्तर (Learning Outcomes) शहरी एवं अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों की तुलना में कमजोर पाई जाती हैं। यह असमानता मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया को असंतुलित बनाती है और विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में एक प्रमुख बाधा के रूप में उभरती है।

तालिका 2: बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय असमानता

संकेतक	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	स्रोत
साक्षरता दर (%)	लगभग 60	लगभग 75	जनगणना 2011
महिला साक्षरता (%)	लगभग 50	लगभग 70	जनगणना 2011
प्रशिक्षित शिक्षकों का अनुपात (%)	कम	अधिक	UDISE+
छात्र–शिक्षक अनुपात	अधिक (भीड़)	तुलनात्मक रूप से कम	UDISE+
कंप्यूटर/डिजिटल सुविधा युक्त विद्यालय (%)	सीमित	अपेक्षाकृत अधिक	UDISE+
उच्च माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता	कम	अधिक	राज्य शिक्षा विभाग

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर स्थानिक रूप से अत्यंत असमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर और विशेषकर महिला साक्षरता का निम्न स्तर यह संकेत देता है कि शिक्षा तक समान अवसर उपलब्ध नहीं हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और उच्च छात्र–शिक्षक अनुपात के कारण शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे विद्यार्थियों के बुनियादी कौशल और शैक्षणिक उपलब्धियाँ कमजोर रहती हैं। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर अवसंरचना, डिजिटल सुविधाएँ और शिक्षकों की उपलब्धता के कारण शिक्षा की गुणवत्ता अपेक्षाकृत उच्च पाई जाती है।

यह क्षेत्रीय असमानता मानव संसाधन विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, क्योंकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा रोजगारोन्मुख कौशल प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं। परिणामस्वरूप, राज्य में असंतुलित मानव संसाधन विकास, शिक्षित बेरोजगारी तथा बाह्य प्रवासन जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अतः विकसित भारत 2047 के संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु क्षेत्र–विशिष्ट नीतियाँ, प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती, डिजिटल अवसंरचना का विस्तार तथा ग्रामीण–शहरी अंतर को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

- **तकनीकी एवं कौशल–आधारित शिक्षा का अपर्याप्त विस्तार**

बिहार में मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी एवं कौशल–आधारित शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान वैश्विक एवं राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में रोजगार के अवसर तेजी से तकनीक, नवाचार और विशिष्ट कौशल पर आधारित होते जा रहे हैं। किंतु बिहार में उच्च, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप, राज्य की विशाल युवा जनसंख्या पर्याप्त कौशल के अभाव में उत्पादक मानव संसाधन में परिवर्तित नहीं हो पा रही है, जिससे विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है।

तालिका 3: बिहार में तकनीकी एवं कौशल–आधारित शिक्षा की स्थिति

संकेतक	बिहार	भारत (औसत)	स्रोत
उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात (GER, %)	~17	~28	AISHE 2021–22
तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों (ITI/Polytechnic) की उपलब्धता	सीमित	अपेक्षाकृत अधिक	कौशल विकास मंत्रालय
कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में युवा भागीदारी	कम	मध्यम	Skill India Reports
उद्योग–शिक्षा समन्वय	कमजोर	तुलनात्मक रूप से बेहतर	नीति आयोग

रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की उपलब्धता	सीमित	अधिक	राज्य/राष्ट्रीय शिक्षा रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में तकनीकी एवं कौशल–आधारित शिक्षा की पहुँच और सहभागिता राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। उच्च शिक्षा में निम्न GER यह संकेत करता है कि बड़ी संख्या में युवा उच्च, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा से बाहर रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ITI, पॉलिटेक्निक तथा अन्य कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की सीमित संख्या और उनका असमान भौगोलिक वितरण ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है।

उद्योग–शिक्षा समन्वय के अभाव में पाठ्यक्रम श्रम–बाजार की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो पाते, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर बाह्य प्रवासन की स्थिति उत्पन्न होती है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कम कवरेज यह दर्शाती है कि बिहार की जनसांख्यिकीय क्षमता अभी भी पर्याप्त रूप से उपयोग में नहीं लाई जा सकी है। अतः विकसित भारत @2047 के परिप्रेक्ष्य में यह अनिवार्य है कि बिहार में तकनीकी एवं कौशल–आधारित शिक्षा का व्यापक विस्तार किया जाए, उद्योग–शिक्षा साझेदारी को सुदृढ़ किया जाए तथा रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि राज्य की युवा शक्ति को प्रभावी मानव संसाधन में रूपांतरित किया जा सके।

- **महिला शिक्षा एवं कार्यबल भागीदारी में बाधाएँ**

बिहार में मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में महिला शिक्षा और कार्यबल भागीदारी की भूमिका निर्णायक है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि महिला शिक्षा में वृद्धि न केवल श्रम–आपूर्ति और उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, बाल–शिक्षा और सामाजिक समानता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके बावजूद बिहार में महिला शिक्षा में प्रगति के बावजूद उसका कार्यबल भागीदारी में रूपांतरण अत्यंत सीमित रहा है, जो विकसित भारत @2047 के समावेशी विकास लक्ष्य के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है।

तालिका 4: बिहार में महिला शिक्षा एवं कार्यबल भागीदारी

संकेतक	बिहार	भारत	स्रोत
महिला साक्षरता दर (%)	~53.3	~65.5	जनगणना 2011
उच्च शिक्षा में महिला नामांकन (%)	~47	~49	AISHE 2021–22
महिला कार्यबल भागीदारी दर (%)	~3–6	~25	PLFS / NSSO
ग्रामीण महिला कार्यबल भागीदारी	बहुत कम	मध्यम	PLFS
शहरी महिला कार्यबल भागीदारी	कम	मध्यम	PLFS

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में महिला साक्षरता एवं उच्च शिक्षा में नामांकन के स्तर में वृद्धि हुई है, किंतु इसका आर्थिक सहभागिता में रूपांतरण अत्यंत सीमित रहा है। महिला कार्यबल भागीदारी दर का राष्ट्रीय औसत से बहुत कम होना यह दर्शाता है कि शिक्षा और रोजगार के बीच गहरा अंतर विद्यमान है। इसके पीछे सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंड, घरेलू कार्यों का भार, प्रारंभिक विवाह, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसरों का अभाव प्रमुख कारण हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जहाँ महिला शिक्षा तक पहुँच सीमित होने के साथ–साथ कौशल प्रशिक्षण और रोजगार अवसर अत्यंत न्यून हैं। परिणामस्वरूप, महिला मानव संसाधन क्षमता का बड़ा हिस्सा अव्यवहृत रह जाता है। विकसित भारत @2047 के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि महिला शिक्षा को रोजगारोन्मुख

बनाया जाए, सुरक्षित एवं स्थानीय रोजगार अवसर सृजित किए जाएँ तथा सामाजिक एवं संस्थागत बाधाओं को दूर करने हेतु लक्षित नीतियाँ अपनाई जाएँ, ताकि बिहार में समावेशी मानव संसाधन विकास को गति दी जा सके।

- **डिजिटल विभाजन**

बिहार में शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास की दिशा में डिजिटल तकनीकों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल कौशल, ई–गवर्नेंस तथा सूचना तक त्वरित पहुँच आज के ज्ञान–आधारित समाज की अनिवार्य शर्तें बन चुकी हैं। किंतु बिहार में डिजिटल अवसंरचना, पहुँच और दक्षता में विद्यमान असमानता एक गंभीर डिजिटल विभाजन को जन्म देती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल विकास और रोजगार–योग्यता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह स्थिति विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के लिए एक प्रमुख संरचनात्मक चुनौती के रूप में उभरती है।

तालिका 5: बिहार में डिजिटल विभाजन से संबंधित चयनित संकेतक

संकेतक	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	स्रोत
इंटरनेट सुविधा वाले परिवार (%)	कम	अधिक	NFHS / TRAI
कंप्यूटरध्डिजिटल सुविधा युक्त विद्यालय (%)	सीमित	अपेक्षाकृत अधिक	UDISE+
ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच	बहुत सीमित	बेहतर	शिक्षा विभाग रिपोर्ट
डिजिटल साक्षरता स्तर	निम्न	मध्यम	NSSO
ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म उपयोग	कम	अधिक	राष्ट्रीय शिक्षा रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बिहार में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता स्थानिक रूप से असमान है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल उपकरणों और तकनीकी दक्षता की कमी के कारण विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल प्रशिक्षण और ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म से वंचित रह जाते हैं। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर अवसंरचना के कारण डिजिटल शिक्षा के लाभ अधिक प्राप्त हो रहे हैं।

कोविड–19 महामारी के दौरान यह डिजिटल विभाजन और अधिक स्पष्ट हो गया, जब बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं गरीब परिवारों के विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ नहीं पाए। डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों की सीखने–सिखाने की क्षमता को सीमित करता है, जिससे मानव संसाधन विकास की गति प्रभावित होती है। अतः विकसित भारत @2047 के संदर्भ में यह आवश्यक है कि बिहार में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, सस्ती इंटरनेट सुविधा, विद्यालयों में डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता तथा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि डिजिटल विभाजन को कम कर समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास सुनिश्चित किया जा सके।

- **शिक्षा और रोजगार के बीच सामंजस्य का अभाव**

बिहार में मानव संसाधन विकास की एक प्रमुख चुनौती शिक्षा और रोजगार के बीच प्रभावी सामंजस्य का अभाव है। राज्य में शिक्षा के स्तर में क्रमिक वृद्धि के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षित युवा उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति इस तथ्य को दर्शाती है कि शिक्षा प्रणाली द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल श्रम–बाजार की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। परिणामस्वरूप, एक ओर शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, तो दूसरी ओर उद्योगों को उपयुक्त कौशलयुक्त मानव शक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह असंतुलन विकसित भारत @2047 के रोजगारोन्मुख एवं आत्मनिर्भर विकास लक्ष्य के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है।

तालिका 6: बिहार में शिक्षा–रोजगार असंतुलन से संबंधित चयनित संकेतक

संकेतक	बिहार की स्थिति	तुलनात्मक स्थिति (भारत)	स्रोत
शिक्षित बेरोजगारी दर	उच्च	मध्यम	PLFS / NSSO
युवाओं का बाह्य प्रवासन	बहुत अधिक	अपेक्षाकृत कम	Census / राज्य रिपोर्ट
उच्च शिक्षा GER (%)	~17	~28	AISHE 2021–22
कौशल–आधारित रोजगार अवसर	सीमित	अधिक	नीति आयोग
उद्योग–शिक्षा सहयोग	कमजोर	तुलनात्मक रूप से बेहतर	नीति आयोग / शिक्षा मंत्रालय

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बिहार में उच्च शिक्षा में भागीदारी (GER) का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, वहीं जो युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें भी रोजगारोन्मुख कौशल का अभाव पाया जाता है। पाठ्यक्रमों का उद्योग एवं बाजार की बदलती आवश्यकताओं से समन्वय न होना, व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप के अवसरों की कमी तथा स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास का अभाव ये सभी कारक शिक्षा–रोजगार असंतुलन को और गहरा करते हैं।

इस असंतुलन का प्रत्यक्ष परिणाम बड़े पैमाने पर बाह्य प्रवासन के रूप में दिखाई देता है, जहाँ शिक्षित एवं अर्द्ध–शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर पलायन करने को विवश होते हैं। इससे न केवल बिहार की स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, बल्कि राज्य में मानव संसाधन विकास का लाभ अन्य क्षेत्रों को प्राप्त होता है। अतः विकसित भारत @2047 के संदर्भ में यह आवश्यक है कि बिहार में शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख, कौशल–आधारित और उद्योग–संलग्न बनाया जाए, ताकि शिक्षा और रोजगार के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित कर राज्य की युवा शक्ति को स्थानीय एवं राष्ट्रीय विकास में सार्थक रूप से समाहित किया जा सके।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल विकास, लैंगिक समानता, डिजिटल पहुँच और शिक्षा–रोजगार समन्वय ये सभी आयाम बिहार में मानव संसाधन विकास की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। यदि विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इन चुनौतियों का समाधान समन्वित, डेटा–आधारित एवं क्षेत्र–विशिष्ट नीतियों के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

संभावनाएँ एवं विकास की दिशाएँ

(1) विशाल युवा जनसंख्या

बिहार की जनसंख्या संरचना में युवाओं का अनुपात अत्यधिक है, जो राज्य को एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करता है। यदि इस युवा शक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी दक्षता और रोजगारोन्मुख कौशल से सुसज्जित किया जाए, तो यह न केवल बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकती है, बल्कि राज्य की आर्थिक उत्पादकता को भी तीव्र गति प्रदान कर सकती है। यह युवा वर्ग बिहार को विकसित भारत @2047 की दिशा में अग्रसर करने का सबसे मजबूत आधार बन सकता है।

(2) डिजिटल एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार की संभावनाएँ

डिजिटल क्रांति ने शिक्षा और मानव संसाधन विकास के नए द्वार खोले हैं। बिहार में ऑनलाइन शिक्षा, ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल कक्षाओं और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार से क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया अधिक समावेशी बन सकती है।

(3) कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा

कौशल विकास बिहार में मानव संसाधन विकास की सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक है। राज्य में यदि व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी कौशल, स्टार्ट–अप और स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाए, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन संभव है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बना सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा मिलेगा।

(4) महिला शिक्षा और सशक्तिकरण

महिला शिक्षा बिहार में मानव संसाधन विकास की गति को बहुगुणित करने वाली क्षमता रखती है। शिक्षित महिलाएँ कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के साथ–साथ परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों की शिक्षा में भी सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। महिला शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित कर राज्य में लैंगिक समानता और समावेशी विकास को सुदृढ़ किया जा सकता है, जो विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है।

(5) ग्रामीण–शहरी संतुलित विकास

मानव संसाधन विकास के लिए ग्रामीण–शहरी संतुलित विकास अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान रूप से उपलब्ध कराए जाएँ, तो क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सकता है। इससे न केवल ग्रामीण युवाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि राज्य के समग्र विकास में संतुलन और स्थायित्व भी सुनिश्चित होगा।

नीति–निहितार्थ एवं सुझाव

प्रथम, बिहार में मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ करने हेतु शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता सुधार को नीतिगत प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति, नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यालयों की भौतिक एवं शैक्षणिक अवसंरचना का उन्नयन तथा अधिगम–परिणाम (Learning Outcomes) आधारित मूल्यांकन प्रणाली को लागू करना आवश्यक है। इससे क्षेत्रीय शैक्षिक असमानताओं को कम किया जा सकेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

द्वितीय, तकनीकी एवं कौशल–आधारित शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य को उद्योग–शिक्षा समन्वय को सुदृढ़ करना चाहिए। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या और भौगोलिक पहुँच बढ़ाने के साथ–साथ पाठ्यक्रमों को श्रम–बाजार की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन करना आवश्यक है। इससे युवाओं की रोजगार–योग्यता में वृद्धि होगी और शिक्षित बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी।

तृतीय, महिला शिक्षा एवं कार्यबल भागीदारी बढ़ाने हेतु लैंगिक–संवेदनशील नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, सुरक्षित एवं स्थानीय रोजगार अवसरों का सृजन, कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी, तथा सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं। इससे समावेशी मानव संसाधन विकास को गति मिलेगी।

चतुर्थ, डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए डिजिटल अवसंरचना एवं साक्षरता के विस्तार पर विशेष ध्यान देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा, विद्यालयों में डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता, तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। यह कदम डिजिटल शिक्षा और तकनीकी दक्षता को व्यापक बनाएगा।

पंचम, शिक्षा और रोजगार के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए रोजगारोन्मुख शिक्षा नीति अपनाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, स्थानीय उद्योगों से साझेदारी और उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा प्राप्त मानव संसाधन का लाभ राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त हो सके।

इस प्रकार, उपर्युक्त नीतिगत निहितार्थों और सुझावों के प्रभावी क्रियान्वयन से बिहार में मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ किया जा सकता है और राज्य को विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक सशक्त सहभागी बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि बिहार में मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा विकसित भारत @2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए मूलभूत एवं निर्णायक स्तंभ हैं। यद्यपि राज्य में शिक्षा के प्रसार, नामांकन एवं साक्षरता में प्रगति हुई है, फिर भी शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय असमानता, तकनीकी एवं कौशल–आधारित शिक्षा का सीमित विस्तार, महिला शिक्षा और कार्यबल भागीदारी में बाधाएँ, डिजिटल विभाजन तथा शिक्षा–रोजगार असंतुलन जैसी चुनौतियाँ मानव संसाधन क्षमता के पूर्ण उपयोग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। दूसरी ओर, विशाल युवा जनसंख्या, डिजिटल एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार की संभावनाएँ, कौशल विकास एवं उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण–शहरी संतुलित विकास जैसे कारक बिहार को एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करते हैं। यदि शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण, कौशल एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, डिजिटल समावेशन और समावेशी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, तो बिहार न केवल अपनी आंतरिक विकासात्मक चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित कर सकता है, बल्कि विकसित भारत @2047 की यात्रा में एक सशक्त, सक्रिय और दीर्घकालिक योगदानकर्ता के रूप में उभर सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार (2011). भारत की जनगणना 2011 : प्राथमिक जनगणना सार. नई दिल्ली : भारत सरकार।
2. भारत सरकार (2021–22). अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE). नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग।
3. नीति आयोग (2021). भारत /2047 : विकसित भारत का दृष्टिकोण पत्र. नई दिल्ली : नीति आयोग, भारत सरकार।
4. भारत सरकार (2023). आर्थिक सर्वेक्षण. नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
5. भारत सरकार (2022). आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS). नई दिल्ली : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
6. भारत सरकार (2023). UDISE+ रिपोर्ट : विद्यालय शिक्षा की स्थिति. नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
7. शुल्त्ज, टी. डब्ल्यू. (1961). मानव पूँजी में निवेश. अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, 51(1), 1–17.
8. बेकर, जी. एस. (1964). मानव पूँजी : शिक्षा में निवेश का सैद्धांतिक विश्लेषण. न्यूयॉर्क : कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. सेन, अमर्त्य (1999). विकास एक स्वतंत्रता के रूप में. नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. द्रेज, जीन एवं सेन, अमर्त्य (2013). भारत : विकास की संभावनाएँ और चुनौतियाँ. नई दिल्ली : पेंगुइन बुक्स इंडिया।
11. भारत सरकार (2022). डिजिटल इंडिया पहल : प्रगति रिपोर्ट. नई दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

12. भारत सरकार (2021). कौशल भारत मिशन : वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली : कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।
13. कुमार, आर. (2016). बिहार में शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. पटना : बिहार राज्य अभिलेखागार।
14. सिंह, एस. (2019). बिहार में महिला शिक्षा एवं रोजगार की स्थिति. भारतीय सामाजिक अनुसंधान पत्रिका, 45(2), 112–128।
15. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) (2022). मानव विकास रिपोर्ट. न्यूयॉर्क : UNDP।